



## स्पष्टीकरण

Posted On: 19 JUN 2017 5:25PM by PIB Delhi

केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय का हवाला देकर जमीन संबंधी अभिलेखों के डिजिटिलाइजेशन और उसे आधार (AADHAR) से जोड़ने से सम्बंधित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया जा रहा पत्र पूरी तरह से फर्जी है और ऐसा शरारतपूर्ण किया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार ने इस तरह का कोई पत्र जारी नहीं किया है। इस संदर्भ में पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई गई है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

\*\*\*

ΑK

(Release ID: 1493284) Visitor Counter: 18

f







in